पृष्ठ : 04
स्थापित : 2008
संस्थापक: स्व. बी. शंकर
11 जुलाई 2025, शुक्रवार
संपादक: गंगा असनोड़ा: 9412079290

सरोकारों से साक्षात्कार

रीजनल रिपोर्टर

श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तराखण्ड से प्रकाशित, साप्ताहिक आर.एन.आई.नं: UTTHIN/2008/24749, वर्ष: 17, अंक: 04, मूल्य: 10

त्रिस्तरीय पंचायतों में दो जगह नाम होने पर प्रत्याशी अयोग्य

रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची में प्रत्याशियों तथा मतदाताओं के दो-दो जगह नाम होने को उच्च न्यायालय ने पंचायत राज अधिनियम के विरूद्ध बताया है। उच्च न्यायालय ने इस मसले पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दो-दो जगह नाम होने के बावजूद प्रत्याशियों तथा मतदाताओं को चुनाव लड़ने तथा मतदान का अधिकार दिए जाने के निर्णय को खारिज कर दिया है।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में गढ़वाल के शक्ति सिंह बर्त्वाल की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी के अनुसार कोर्ट के आदेश के बाद दो मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए हैं, यदि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो यह अवमानना के दायरे में आएगा।

धारगांव की निर्विरोध प्रत्याशी शिवानी की उम्र निकली कम

टिहरी जिले के भिलंगना विकासखंड की भिल्लंग पट्टी के धारगांव ग्राम सभा ने आम बैठक कर शिवानी राणा को निर्विरोध ग्राम प्रधान चुन लिया। प्रस्ताव पास किया और नामांकन पत्र भी भरा गया, लेकिन शिवानी की उम्र 3 महीने कम निकली। उसे 21 वर्ष पूरे होने के लिए 16 अक्टूबर 2025 तक इंतजार करना होगा। क्योंकि 16 अक्टूबर 2004 शिवानी की जन्मतिथि है।

ग्राम सभा से किसी और ने भी नामांकन नहीं किया। ग्राम प्रधान पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में फिलहाल प्रधान की सीट खाली रह जाएगी। हालांकि ग्रामीणों ने आगामी चुनावों में शिवानी को ही ग्राम प्रधान चुना जाएगा।

बामसू गांव में पांच वार्ड सदस्य निर्विरोध निर्वाचित

रूद्रप्रयाग के बामसू गांव में पांच वार्ड सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। वार्ड एक से नरीता देवी, वार्ड दो से साक्षी कंडारी, वार्ड तीन से ललिता देवी, वार्ड चार से शकुंतला देवी, वार्ड पांच से बालम सिंह निर्विरोध वार्ड सदस्य चुन लिए गए हैं।

लॉटरी से बीडीसी सदस्य का निर्विरोध चयन

टिहरी जिले के चंबा विकासखंड के नकोट मखलोगी क्षेत्र पंचायत वार्ड में 6 उम्मीदवारों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य की दावेदारी की। पर्चे भी भर दिये गये। सीट अनारक्षित है। पर्चे भरने वालों में निवर्तमान प्रमुख भी शामिल थी। कुछ लोगों ने कोशिश की, बीडीसी सदस्य भी निर्विरोध बना लिया जाए।

विचार आया कि क्यों ना पर्ची बनाई जाए और लॉटरी में जिसका नाम आएगा, उसी को निर्विरोध बना लिया जाए। इस पर सभी छह उम्मीदवार सहमत भी हो गए। पर्ची सरोज मखलोगा के पक्ष में निकल गई।

जिन छह लोगों ने नामांकन किया और हिम्मत के साथ लॉटरी के पक्ष में सहमति दी, वे हैं - शिवानी बिष्ट निवर्तमान प्रमुख, दिनेश चंद्र भट्ट पूर्व बीडीसी मेंबर, मकान सिंह व भगवान सिंह बिष्ट पूर्व ग्राम प्रधान और गौतम मखलोगा। बाकी पांच ने नाम वापसी प्रपत्र भर दिये हैं। ■■■

एनईपी 2020 पर 50 विवि के कुलपतियों ने रखी बात

स्टेट ब्यूरो

10 जुलाई 2025 से गुजरात केवड़िया में आयोजित वाईस चांसलर कॉनफ्रेंस में देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 50 से अधिक कुलपति एक मंच पर एकत्र हुए, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया।

इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह ने भी सक्रिय सहभागिता की। उन्होंने "विकसित भारत 2047" की दिशा में एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन पर विचार साझा किए।

धर्मेंद्र प्रधान ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि एनईपी 2020 अब केवल नीति नहीं, बल्कि "पंच संकल्प" के रूप में एक प्रेरक शक्ति है-अगली पीढ़ी की शिक्षा, बहु-विषयकता, नवाचार, समग्रता और भारतीयता।

उन्होंने उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत जीईआर लक्ष्य, छात्र-प्रथम दृष्टिकोण, बहु-विषयक पाठ्यक्रम, डिजिटल लर्निंग, आईकेएस और समानता पर केंद्रित सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया।

पहले दिन की चर्चाएं रणनीतिक योजना, कार्यबल विकास, डिजिटल रूपांतरण, समावेशिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को केंद्र में रखकर हुईं। इस अवसर पर यह भी तय किया गया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय एनईपी 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपना रणनीति पत्र तैयार करेगा।

यह सम्मेलन भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को सशक्त, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। ■■■

महेश गिरी बने महंत

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नागेश्वर महादेव मंदिर के महंत

नितिन पुरी ने कटकेश्वर महादेव के पुजारी महेश गिरी को महंत की दीक्षा दी।

इस अवसर पर महंत नितिन पुरी ने विधि-विधान से महेश गिरि को दसनामी गोस्वामी समाज के परम्परानुसार गुरु मंत्र देकर महंत परम्परा में शामिल किया।

दसनामी , शैव (शिव उपासक) संन्यासियों से जुड़ा एक समुदाय है।

दसनामी संप्रदाय के संन्यासी/गृहस्थ दस नामों में से एक नाम अपनाते हैं, जैसे गिरि, पुरी, भारती, वन/बान, अरण्य, सागर, आश्रम, सरस्वती, तीर्थ और पर्वत। ■■■

श्रीनगर में लगातार दो दिन गुलदार का हमला

रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो

श्रीनगर-पौड़ी मार्ग पर गंगादर्शन के समीप लगातार दो दिनों में दो लोगों पर गुलदार के हमले से क्षेत्र में दहशत बढ़ गई है।

श्रीनगर-पौड़ी नेशनल हाईवे पर भ्रमण करने वाले श्रीनगर के दो लोगों पर गुलदार के वार से इस मार्ग पर दुपहिया वाहनों पर रोजमर्रा में आवाजाही करने वाले लोग भयभीत है।

गौरतलब है कि, श्रीनगर से पौड़ी तथा पौड़ी से श्रीनगर अपने-अपने कार्यों के लिए हर रोज सैकड़ों लोग पौड़ी श्रीनगर मार्ग पर दुपहिया वाहनों से चलते हैं। ऐसे में गुलदार की दहशत ने लोगों को डरा दिया है।

श्रीनगर-पौड़ी मोटर मार्ग स्थित गंगा दर्शन मोड़ पर घटित हुई, जब उफल्डा वार्ड नंबर 38 निवासी 32 वर्षीय रोबिन कैतूरा शाम लगभग 7:30 बजे टहलने गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक जब सड़क किनारे से गुजर रहा था, तभी झाड़ियों में छिपे गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। रोबिन ने बहादुरी दिखाते हुए शोर मचाया, जिससे वहां मौजूद राहगीरों और रेस्टोरेंट कर्मियों ने मदद कर गुलदार को भगाया।

गुलदार के हमले में रोबिन के सिर, पीठ और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत संयुक्त अस्पताल श्रीनगर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को स्थिर लेकिन गहन निगरानी योग्य बताया है। घायल को अस्पताल पहुंचाने में रेस्टोरेंट कर्मी सोनू ने अहम भूमिका निभाई।

दूसरे ही दिन करीब साढ़े छह बजे आंचल डेयरी निवासी 39 वर्षीय जयदेव सिंह रावत रोज की तरह गंगा दर्शन बैंड के पास टहल रहे थे। उसी दौरान एक गुलदार अचानक सड़क के ऊपर पहाड़ी से छलांग लगाकर उन पर झपट पड़ा। जयदेव सिंह ने साहस दिखाते हुए गुलदार से संघर्ष किया और आसपास टहल रहे युवाओं की मदद से किसी तरह अपनी जान बचाई।

वन विभाग ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वन्यजीव गतिविधियों पर निगरानी के लिए विशेष टीम को इलाके में भेजा गया है। विभाग जल्द ही क्षेत्र में पिंजरा लगाने और रात्रि गश्त बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकें। ■■■

शेखर पाठक को 16वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति-सम्मान

वीरेन नंदा

प्रो. शेखर पाठक को यह सम्मान उनकी नवीनतम पुस्तक 'हिमांक और क्वथनांक के बीच' के लिए प्रदान किया जाएगा। पुस्तक एक अनूठे हिमालयी यात्रा वृत्तांत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने गंगोत्री-कालिंदीखाल और बदरीनाथ की दुर्गम यात्रा का सजीव चित्रण किया है।

अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति समिति के अध्यक्ष वीर भारत तलवार ने इस सम्मान की घोषणा की। यह पुरस्कार हल्द्वानी में आयोजित एक समारोह में नवंबर 2025 में औपचारिक रूप से प्रदान किया जाएगा।

'हिमांक और क्वथनांक के बीच' केवल एक यात्रा-वृत्तांत नहीं, बल्कि हिमालय की पारिस्थितिकी, संघर्षशील जीवनशैली और को दर्शाती है।

यह कृति गंगोत्री-कालिंदीखाल और बदरीनाथ की दिल दहला देने वाली दुस्साहसिक यात्रा वृतांत है, जिसमें हिमालय की नैसर्गिक सुंदरता, हिम और गल की अनसुनी-अनजानी आवाज और अनचीन्हे पशु-पक्षियों के दर्शन तो होते ही है, मौत से मुलाकात भी। क्योंकि इस यात्रा में उन्हें अपने इतने करीब मौत की परियाँ पहले कभी नाचते हुए महसूस नहीं हुई थीं।

आदिम राग गाते हिमालय के इस अनजाने रास्ते पर यात्रा करने का जोखिम उठाने वाले शेखर पाठक ने इस पुस्तक में अतीत में पहली बार इस मार्ग से यात्रा करने वाले उन पर्वतारोहियों के इतिहास, उनके संघर्ष तथा उनके रचे साहित्य का उल्लेख है। दूसरी ओर उस इलाके में रहने वाले उन कुलियों का भी मार्मिक चित्रण किया है, जिन्हें बेगारी पर खून जमा देने वाली ठंड में नंगे पाँव चलना पड़ता था। इसके बावजूद इन्होंने फिर फिर यात्राएँ की। मानसरोवर और नेपाल से सटे पूर्वी उत्तराखण्ड से पश्चिम उत्तराखण्ड तथा लेह से अरुणाचल तक की यात्रा शामिल है। ■■■

SUBSCRIBE

संपादकीय

नासूर बन जाएगी यह चुप्पी...

उत्तराखंड में शिक्षा विभाग प्रयोगों की खान रही है। इन प्रयोगों के बीच विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी किस कदर पिस रहे हैं, इससे न ही शिक्षा विभाग को कोई मतलब रहा है और न ही राज्य सरकार और उनके मंत्रियों को ही कोई मतलब रहा है।

राज्य बनने के बाद उत्तराखंड को मिले शिक्षा मंत्री अपना काम बनाने से अधिक कुछ नहीं सोच पाए। अपना काम बनाने की प्रवृत्ति में अपने आदमियों को शिक्षा विभाग में घुसाने से लेकर भ्रष्टाचार का चरम सुख भोगने तक की व्यवस्था शामिल रही है।

पढ़ाने के अतिरिक्त कई-कई अन्य कार्यों के बोझ तले दबे शिक्षकों की मजाल नहीं है कि वे अपनी सरकार और विभाग के समक्ष चूं भी कर सकें। बीते दिनों गोपेश्वर से सुर्खियों में आया मामला शिक्षकों की फजीहत और परेशानी को बयां करने के लिए काफी है।

बीते वर्ष में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में किए जाने और फिर एक साथ सभी विद्यालयों का परीक्षाफल खराब होने की स्थिति में ठीकरा शिक्षकों के सिर फोड़ने का मामला भी आया। अपनी प्रयोगशाला में शिक्षा विभाग को पुनः इन विद्यालयों को हिन्दी मीडियम करने निर्णय लेकर प्रयोग वापस करना पड़ा।

त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव छह माह देरी से हो रहे हैं। उस पर दो बार पंचायत चुनावों से जुड़े विषयों पर असंतुष्ट उच्च न्यायालय की शरण ले चुके हैं। पहली बार उच्च न्यायालय ने तीन दिनों तक चुनाव की प्रक्रिया को रोका, लेकिन फिर स्थागनादेश वापस ले लिया।

अब एक बार फिर दो-दो स्थानों पर मतदाताओं तथा प्रत्याशियों का मतदाता सूची में नाम होने का मसला उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिस पर उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट आदेश दिया है कि दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम होने पर प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किए जाएं।

इन्हीं चुनावों में कई अतिथि शिक्षकों की भी चुनाव ड्यूटी लगाई गई है। इन अतिथि शिक्षकों को चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का कार्य सौंपा गया है। उत्तराखंड में प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ इस राज्य की सरकारों ने जो किया है, वह अक्षम्य अपराध से कम नहीं। युवा बेरोजगारों का मानसिक और आर्थिक शोषण आए दिन की बात हो गई है। बेरोजगार संगठन इन युवाओं को शायद ही कभी इस हताशा से बाहर निकाल पाए, क्योंकि बेरोजगार स्वयं अपने अधिकारों के लिए दो टूक बात करने को तैयार नहीं हैं।

युवा बेरोजगारों का इस तरह चुपचाप मानसिक और आर्थिक शोषण सह जाना आने वाली पीढ़ी के लिए नासूर बन जाएगा।

■■■

काफल के बाद अब आई जामुन की बारी

अमृता गिरीश

खट्टा-मीठा स्वाद लिए जामुन यानी ब्लैकबेरी, काफल का सीजन खत्म होते ही आ जाते हैं। आयरन, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का बेहतरीन स्रोत जामुन शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाने वाला होता है। यह इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ाता है और ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। एंटी बैक्टीरियल गुण भी इसमें है। पोटैशियम की भरपूर मात्रा होने के कारण दिल को मजबूत बनाता है। ये तो रहे जामुन के कुछ फायदे।

और अब मगरमच्छ, बंदर और जामुन वाली कहानी। जिसे हमारे समय में भी पंचतंत्र की कहानियां सुनने वाले बच्चे खूब चाव से सुनते थे और आज भी ऑडियो-वीडियो के माध्यम से और रंग-बिरंगी पुस्तकों के माध्यम से यह कहानी बच्चों के बीच में लोकप्रिय है। मुझे मेरी मम्मी बहुत ही रोचक तरीके से इस कहानी को सुनाया करती थीं। कहानी कुछ यूं है - एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बन्दर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे-मीठे जामुन लगते थे। नदी में एक मगरमच्छ रहता था और बंदर की उससे मित्रता हो गयी। बन्दर मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता था।

एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाये। पत्नी ने सोचा जो इतने मीठा जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। उसने अपने मगरमच्छ से कहा कि उसे उस बन्दर का कलेजा चाहिए और वह इसी जिद पर अड़ गई।

मगरमच्छ की भी तो आखिर इंसान का ही एक रूप है। पत्नी की जिद के आगे मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल के तहत बन्दर से कहा कि उसकी भाभी ने उसके लिए दावत का इन्तजाम किया है। दावत के नाम पर बन्दर खुश। पर समस्या यह थी कि कि वो भला नदी में कैसे जा पाता? उसे तो तैरना ही नहीं आता था। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठकर नदी में पहुंच जाए। बंदर को विचार पसंद आया और अपने मित्र की बात का भरोसा कर, पेड़ से नदी में कूद कर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों-बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने बन्दर को सही बात बता दी। उसने भेद खोलते हुए कहा कि उसकी पत्नी कह रही थी की जो इतने मीठे जामुन खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। यह सुनकर बन्दर खतरा भांप गया लेकिन उसने समझदारी से काम लिया।

वह तपाक से बोला, "ओह मेरे मित्र! यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैं तो अपना कलेजा जामुन के पेड़ में ही सम्भाल कर रख आया हूँ। जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं पेड़ से उसे लाकर भाभी को तोहफे में दे सकूं।" मूर्ख मगरमच्छ बन्दर को जैसे ही नदी के किनारे ले कर आया, बन्दर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और चिढ़ाते हुए बोला, "मूर्ख, कलेजा भी किसी का कहीं पेड़ में रहता है ?"

■■■

भाषा जरूरी या संवाद

नीमा पाठक

हैदराबाद से आई एक छोटी सी बच्ची फोन पर पर अपनी दोस्त से बड़ी सहजता से तेलगु में बात

कर रही थी। मैंने पूछा कौन सी भाषा में बात कर रही थी? उसका उत्तर था, भाषा थोड़ी बोल रही थी, मैं तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी! इतनी छोटी बच्ची भाषाओं के नाम नहीं जानती थी पर बोल सकती थी। बच्चों में भाषा सीखने का कौशल अद्भुत होता है वह लिखाने-पढ़ने से पहले ही बोलचाल से ही भाषा सीख जाते हैं।

ऐसे में मराठी भाषा के पैरोकार बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में हिंदी पढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। जबकि प्राथमिक विद्यालय में ही भाषाओं का परिचय कराना चाहिए। मराठी और हिंदी दोनों की लिपि भी देवनागरी ही है।

भाषा का राजनीतिकरण करके अपने अस्तित्व को बचाने की मुहिम में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये लोग अपने बच्चों के लिए तो हिंदी के ट्यूशन रख लेते हैं, लेकिन विद्यालय में विरोध करते हैं। भाषा संवाद का माध्यम है उसे किसी पर जबरन थोपा नहीं जाना चाहिए, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है किसी भाषा विशेष को बोलने के लिए पर जिस बेरहमी से लात घूंसे मार कर लोगों को मराठी नहीं आने पर दंडित किया जा रहा है वह बेहद निंदनीय है। ■■■

बहुप्रतीक्षित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच ग्राम स्वराज की खोखली होती कल्पना

चारु तिवारी

उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। गांव से लेकर सोशल मीडिया तक अब पंचायत चुनाव के ही चर्चे हैं। अपनी-अपनी व्याख्या, अपने-अपने आंकलन। चटकारे लेकर किस्से-कहानियां और मीम्स बनाए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में इस तरह के कुछ मीम्स बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं- 'ग्राम प्रधान ने हल्द्वानी-कोटद्वार में दूसरा मकान बनाने की तैयारी कर ली है। 'ग्राम प्रधान ने पिछले कार्यकाल में जमीन खरीद ली थी, इस चुनाव में मकान बन जाएगा'। 'शहर से ब्वारी भी प्रधान बनने गांव आ रही है'। कई लघु फिल्में और वीडियो बन रहे हैं। इन सब में बताया जा रहा है कि किस तरह पंचायत चुनावों में पैसा-शराब-संसाधनों का बोलबाला होता है। ग्राम प्रधान बनने के लिए लोग शहरों से घर आ रहे हैं। जीतने के लिए लोग शहरों से वोटरों को गाड़ियों में ला रहे हैं। लब्बोलुआब सभी का यही है कि पंचायत चुनाव गांव के विकास के लिए नहीं, बल्कि लूट तंत्र है। पंचायतों के बारे में इस तरह की समझ बनना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह बताता है कि जिस पंचायती राज के माध्यम से 'स्थानीय सरकार' की कल्पना की गई थी वह कितनी खोखली साबित हुई। यह भी कह सकते हैं कि अपने लोकतांत्रिक हकों के लिए भारत जैसे देश में विकास के विकेन्द्रीकरण के दर्शन से जिन पंचायतों को संवैधानिक अधिकारों से समृद्ध होना था वे सरकारों, पार्टियों और नागरिकों की उपेक्षा से अपनी अस्मिता भी खो रहे हैं। सरकारें और राजनीतिक दल कभी नहीं चाहते कि अधिकारों का विकेन्द्रीकरण हो। जिस दिन ग्राम पंचायतें अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगी, केन्द्रीकृत व्यवस्था से लूट के रास्ते बंद हो जायेंगे। इसलिए यह सही समय है जब मीम्स और चटकारे लेकर पंचायतों को गलियाने की बजाए पंचायत चुनाव के आलोक में एक बार 'ग्राम स्वराज', 'ग्राम सरकार' 'ग्राम गणराज्य' या 'स्थानीय सरकार' के बारे में सोचा जाये।

सरकारों ने पंचायती राज जैसे विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को बहुत तरीके से भ्रष्ट और नकारा बताने की साजिश की है। उसे इस बात से समझा जा सकता है कि आजादी के इतने सालों बाद भी पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत करने की मांग करने की बजाए उसे मजाक का विषय बना दिया गया है। जब भी पंचायती राज के सही स्वरूप की बात होती है तो यही बात कही जाती है कि ग्राम प्रधान ही भ्रष्ट हैं तो क्या किया जा सकता है। यह उस तरह का सच नहीं है जैसा दिखया-बताया जा रहा है। यह सच है कि राजनीतिक पार्टियों ने पूरे देश में भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपसंस्कृति का जो रास्ता तैयार किया है उसका सबसे छोटा पुर्जा ग्राम प्रधान जरूर है, लेकिन यह उसका बनाया रास्ता नहीं है। पहली बात तो यह है कि सरकारों के तमाम दावों के बावजूद हकीकत यह है कि ग्राम पंचायतें संवैधानिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। देश में जिस तरह से संसाधनों, पैसा और शराब का चलन सत्ता में जाने के लिए किया जाने लगा है, उसका असर ग्राम स्तर पर भी है। सरकारों ने पंचायती राज के नाम पर जो मॉडल दिया वह एक तरह से समाज को विघटित करने वाला साबित हुआ है।

समृद्ध और व्यवसिथत गांवों के लिए पंचायत व्यवस्था को गंभीरता से समझने की जरूरत है। पंचायत समाज की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई है। व्यक्ति, परिवार और उसके ऊपर गांव आता है। इस लिहाज से देखें तो पंचायती राज या 'ग्राम गणराज्य' की मूल इकाई गांव ही हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए 'ग्राम स्वराज' या 'ग्राम सरकार' की परिकल्पना की गई है। उसे संवैधानिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समय-समय पर मांगे भी उठी हैं। कम ज्यादा जो भी हो उसके लिए कुछ प्रावधान भी किये गये हैं। इससे पहले कि पंचायतों के अधिकार की बात करें, एक नजर इसकी उस यात्रा पर भी डालते हैं जो हमें बार-बार इस बात को कहने के लिए बाध्य करती है कि अधिकार संपन्न गांव ही नागरिकों की तकदीर बदल सकते हैं। भारत जैसे देश में पंचायतों का हमेशा से महत्व रहा है। भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन का जिक्र मिलता है। वैदिक काल से लेकर रामायण-महाभारत काल और बाद में मौर्य-गुप्त कालों तक हमें स्थानीय शासन की व्यवस्था मिलती है। आधुनिक काल में स्थानीय निकायों की अवधारणा का विकास हुआ। 1887 में मद्रास में पहला स्थानीय निकाय अस्तित्व में आया, मगर इसका काम अंग्रेजों के रिहाइशी इलाकों में साफ-सफाई करने भर का था। बाद में अंग्रेजों ने गांव पंचायतों का गठन तो किया, लेकिन इन पंचायतों में भी जमींदार अंग्रेजों के हितों को ही साधते रहे। ***क्रमशः*** ■■■

आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है।
अपनी प्रतिक्रिया इस पते पर भेजें।

9412079290, 7037548484

regionalreporter81@gmail.com

श्री कम्यूनिकेशन के लिए गंगा असनोड़ा थपलियाल द्वारा 15 फालतू लाईन, समय साक्ष्य देहरादून से मुद्रित एवं 76, अपर बाजार श्रीनगर से प्रकाशित।
न्यायिक क्षेत्र : श्रीनगर गढ़वाल
संस्थापक संपादक : स्व. बी. शंकर
सलाहकार: वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली
संपादक : गंगा असनोड़ा थपलियाल
विशेष प्रतिनिधि : उमा घिल्डियाल
स्टेट ब्यूरो : भारती जोशी
विशेष प्रतिनिधि (गैरसैण) :
भैरव दत्त असनोड़ा

कार्यालय : श्री कम्यूनिकोशन 76, अपर बाजार, श्रीनगर गढ़वाल-246174
आर.एन.आई.न.-
UPHIN/1999/863

गढ़वाल विवि की प्रो. मंजुला राणा की नियुक्ति पर हाईकोर्ट का नोटिस

स्टेट ब्यूरो

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रो. मंजुला राणा की दोबारा नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। साथ ही, गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत चार अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 319(घ) के उल्लंघन से जुड़ा है।

याचिकाकर्ता डॉ.नवीन प्रकाश नौटियाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि प्रो.मंजुला राणा को वर्ष 2010 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 6 साल यानि की 2016 में पूरा हुआ।

लेकिन कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में नियुक्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 319 (घ) का सीधा उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि इसी विश्वविद्यालय के प्रो. जेएमएस राणा भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य थे, लेकिन उन्हें सेवा समाप्ति के बाद दोबारा विश्वविद्यालय में नियुक्त नहीं किया गया। ऐसे में एक ही संस्थान में दो अलग-अलग मानकों को अपनाना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया गया है।

> **अनुच्छेद 319(घ)** के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य रह चुका हो, उसे दोबारा सरकारी पद या शैक्षणिक संस्थान में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्यायने इस याचिका पर संज्ञान लिया और प्रो. मंजुला राणा को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किया। कोर्ट ने गढ़वाल विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित पक्षों से भी लिखित जवाब तलब किया है। ■■■

संगीता राणा और गौरव कठैत निर्विरोध निर्वाचित

लक्ष्मण सिंह नेगी

ऊखीमठ क्षेत्र पंचायत के जग्गी बगवान बेडूला वार्ड से निर्विरोध निर्वाचित हुई संगीता देवी राणा के गांव पहुँचने पर ग्रामीणो ने फूल - मालाओं से भव्य स्वागत किया।

उन्होंने दोनों गांवों के विभिन्न गांवो का भ्रमण कर जनता का आभार व्यक्त किया तथा ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि जनता ने जिन आशा व उम्मीदों के साथ उन्हें क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सुनहरा अवसर दिया उनका निर्वहन ईमानदारी व आपसी सौहार्द से किया जायेगा । उन्होंने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि गांवो के चहुंमुखी विकास का दायित्व जनता द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधियों का होता है इसलिए क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए त्याग व समर्पण भावना से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा क्षेत्र पंचायतों को आवंटित बजट को जनता की आशाओं के अनुरूप खर्च किया जायेगा तथा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा संघर्षरत रहूंगी।

वहीं दूसरी ओर विकासखंड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत क्यूजा घाटी की ग्राम पंचायत मचकण्डी के प्रधान पद पर निर्विरोध चुने गये गौरव कठैत के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाडो व फूल - मालाओं से भव्य स्वागत किया तथा उन्होने गांव का भ्रमण कर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया ।

उन्होने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मचकण्डी गांव सहित क्यूजा घाटी के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा तथा निष्ठा व निस्वार्थ भावना से क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पबद्ध रहूंगा। नवनिर्वाचित प्रधान गौरव कठैत ने कहा कि तीर्थ स्थलों के चहुंमुखी विकास के लिए जनता को साथ लेकर संघर्ष किया जायेगा तथा प्रदेश सरकार व पर्यटन विभाग से तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के शीतकालीन गद्दीस्थल मक्कूमठ - सौर भूतनाथ- नारायण (मन्दिर तेवडी)- कौलाजीत- कार्तिक स्वामी पैदल ट्रैक को विकसित कर कार्तिक स्वामी पर्यटन सर्किट से जोड़ने की मांग की जायेगी। ■■■

वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में उत्तराखण्ड ने जीते 9 पदक

स्टेट ब्यूरो

उत्तराखंड फायर सर्विस के फायर फाइटर्स ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स-2025 में पहली बार भाग लेकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। पहली बार भाग ले रही टीम ने अपने दमदार प्रदर्शन से कुल नौ पदक जीतकर इतिहास रच दिया, जिनमें दो स्वर्ण, तीन रजत और चार कांस्य पदक शामिल हैं।

भारत की ओर से इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में चार अग्निशमन कर्मियों ने भाग लिया, और विशेष बात यह रही कि ये सभी चार प्रतिभागी उत्तराखंड फायर सर्विस से थे।

फायर सर्विस चालक दिनेश चंद्र भट्ट ने अल्टीमेट फायर फाइटर श्रेणी में रजत और फायर फाइटिंग चौलेंज में कांस्य पदक, महिला फायर फाइटर्स डिंपल, माधुरी भंडारी और पिंकी रावत ने संयुक्त रूप से स्टेयर रन (फुल फायर गियर - महिला टीम) में रजत पदक और अल्टीमेट फायर फाइटर टीम इवेंट में कांस्य पदक, पिंकी रावत को स्टेयर रन (फुल गियर - व्यक्तिगत) में कांस्य पदक, डिंपल ने स्टेयर रन (फुल गियर-मिक्स टीम) और कैजुअल मिक्स टीम में दो स्वर्ण, फुल गियर व्यक्तिगत में रजत और कैजुअल व्यक्तिगत श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया। ■■■

पूर्व सैनिक आश्रितों को नि:शुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण

रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो

पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में नि:शुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी), हरिद्वार के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

इच्छुक अभ्यर्थी 14 जुलाई 2025 तक जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, लैंसडाउन में नामांकन करा सकते हैं। योजनांतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिये कोई शुल्क नहीं देना होगा। ■■■

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जियोथर्मल नीति को मंजूरी

स्टेट ब्यूरो

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पर्यावरण अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल की गई।

- लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य के बी ग्रेड पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड करने के लिए करोड़ों रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई।
- राज्य की पहली जियोथर्मल ऊर्जा नीति 2025 को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई। इस नीति के लागू होने से उत्तराखंड वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में नया अध्याय शुरू करेगा।
- कैबिनेट ने सतर्कता विभाग के ढांचे में संशोधन कर 20 नए पदों को मंजूरी दी है, जिससे विभाग में कुल पदों की संख्या 132 से बढ़कर 152 हो गई है।
- इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध कंपनियों को राज्य में भी सूचना तकनीक से संबंधित सेवाओं और सामग्रियों की आपूर्ति हेतु सूचीबँ किया जाएगा।
- खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन हेतु दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, 2025 और उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास, 2025 को मंजूरी।
- राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना को मंजूरी।
- समाज कल्याण विभाग अब पुत्र के 18 वर्ष का होने पर भी वृद्धावस्था और विधवा पेंशन बाधित नहीं होगी। ■■■

अंकिता हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट में चुनौती

स्टेट ब्यूरो

बहुचचिर्त अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगभग तीन वर्षों की सुनवाई और 47 गवाहों के बयानों के आधार पर, 30 मई 2025 को कोटद्वार की विशेष सत्र अदालत ने पुलकित आर्या सहित तीनों आरोपियों को हत्या, यौन उत्पीड़न और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने माना कि आरोपियों की भूमिका सुनियोजित थी और उन्होंने साक्ष्य को भी मिटाने का प्रयास किया था। इस फैसले को पीड़िता के परिवार और राज्य के नागरिकों ने आंशिक न्याय के रूप में स्वीकार किया।

कोटद्वार कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्य आरोपी पुलकित आर्या ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिसमें 7 जुलाई 2025 को इस अपील पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई की।

बचाव पक्ष ने यह दलील दी कि पूरे मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था और केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सजा दी गई, जो न्यायसंगत नहीं है।

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पुलकित आर्या और अन्य आरोपियों की लोकेशन घटना स्थल के पास पाई गई थी, जिसकी पुष्टि फॉरेंसिक विश्लेषण से हुई है। अंकिता के व्हाट्सएप चैट्स में उन पर दबाव बनाने और आपत्तिजनक प्रस्तावों का उल्लेख मौजूद है। साथ ही, घटना की रात रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए और डीवीआर से छेड़छाड़ की गई, जो साक्ष्य मिटाने का स्पष्ट प्रमाण है।

सुनवाई के बाद खंडपीठ ने निचली अदालत के पूरे रिकॉर्ड को तलब करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 18 नवंबर 2025 तय की है। हाईकोर्ट अब इस बात की समीक्षा करेगा कि क्या निचली अदालत का निर्णय न्यायिक दृष्टि से संतुलित और साक्ष्यों के अनुरूप था या नहीं। ■■■

28 अगस्त से 5 सितंबर भव्य नंदा देवी महोत्सव

उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जुड़ा नंदा देवी महोत्सव इस वर्ष 28 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। नैनीताल में जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इसकी तैयारियों की रूपरेखा तय की गई। यह महोत्सव हर वर्ष भाद्रपद माह में मां नंदा देवी की आराधना के रूप में मनाया जाता है।

इस वर्ष की थीम 'वोकल फॉर लोकल' रखी गई है, जिसका उद्देश्य कुमाऊंनी खानपान, हस्तशिल्प, हथकरघा और पहाड़ी उत्पादों को सम्मानित करना है। जिला प्रशासन ने स्थानीय स्टॉल्स को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है। ■■■

2025-26
REGISTRATION
NOW OPEN
FOR
GRADE 11

The best school in the town with professional service

ABOUT US
The school comes with an uncompromising commitment. It aims to achieve specific measurable observable and quantitable results among all aspirants/students because the school has a vision to provide value based education to young minds and provide a dynamic learning environment.

OUR FACILITIES
The School Provide All Basic Facilities Each Student. Indoor And Outdoor Sports Are Provided By School.
Composite Science Lab
Physics Lab
Chemistry Lab
Biology Lab
Maths Lab
Computer Science Lab
Home Science Lab
Library
Other Rooms

Streams offered:
- Humanities
- Commerce
- Science

Grade Nursery to 12th

Visit our facebook page or website for more
https://www.facebook.com/shemfordSrinagar
srinagar-garhwal.shemford.com

Call To find out more
9568450335, 7895938233

Email
srinagar@shemford.com